THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) to (e) Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) of Japan have appriaised/are appraising the following power projects for a loan package for 1996-97:—

i. Dhauliganga Transmission System (Uttar Pradesh) & Jalandhar (Punjab)—Hamirpur (Himachal Pradesh) Transmission System of Powergrid Corporation of India Limited.

ii. Strengthening of Transmission System of West Bengal.

iii. Renovation & Modernisation Plan of Umiam Stage I Power Station (36 MW), Meghalaya.

iv. Turial Hydro-Electric Project (60 MW), Mizoram.

v. Simhadri Thermal Power Project Stage I (1000 MW), Andhra Pradesh.

vi. Anpara 'C Thermal Power Station Construction Project (1000 MW), Uttar Pradesh.

The final decision about extending loans for these projects would be known only at the time of the meeting of the India Development Forum to be held in September, 1996 in Tokyo (Japan).

Guidelines for the Preparation of the Ninth Plan

1819. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any guidelines in the preparation of the Ninth Five Year Plan;

(b) if so, whether the Planning Commission has prepared a draft model after going through reports of various working groups and steering committees;

(c) if so, the main features of the same; and

(d) by when a final decision is likely to be taken?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) and (b) No, Sir,

(c) and (d) The guidelines for the Ninth Plan will form part of the Approach Paper of the Ninth Five year Plan, which is under process now and is expected to be completed in four months time.

कश्मीर में मारे गये बिहारी मजदूर

1820. श्री रामदेव भंडारी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हाल ही में मारे गये ग्यारह बिहारी मजदूरों तथा अन्य घायल मजदूरों के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार कश्मीर में कार्यरत अन्य राज्यों के मजदूरों की जान-माल की रक्षा हेतु क्या व्यवस्था कर रही है; और

(ग) सरकार मृतक तथा घायल मजदूरों के परिवार वालों के लिये मुआवजा, नौकरी आदि के रूप में क्या-क्या सुविधायें दे रही है?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रमण्यन): (क) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार 6-7 जुलाई 1996 के बीच की रात को कुछ अज्ञात उग्रवादियों ने 18 मजदूरों का अपहरण कर लिया, जो गांव उत्तर-टोला, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और उन्हें जम्मू और कश्मीर में कुपवाड़ा जिले में, हन्डवाड़ा के नजदीक, गांव घोटीपोरा में ईंट के भट्टे में काम पर लगाया गया था।

इनमें से 11 व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी, 5 जख्मी हुए और दो बच कर भाग निकले। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर गए और एक मामला दर्ज किया गया, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है।